



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350]
No. 350]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 20, 2007/कार्तिक 29, 1929
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 20, 2007/KARTIKA 29, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2007

विषय : चीन जन. गण., हांगकांग और ताईवान से डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क-रिकॉर्डेबल (डीवीडी-आर) के आयात के बारे में पाटनरोधी जांच की शुरुआत ।

सं. 14/17/2007-डीजीएडी.—यतः ऑप्टिकल डिस्क मैन्यूफैक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन (ओडीएमडब्ल्यू) नई दिल्ली (जिसे इसके पश्चात् याचिकाकर्ता कहा गया है) ने चीन जन.गण. हांगकांग, और ताईवान (जिसे इसके पश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क-रिकॉर्डेबल (डीवीडी-आर) (जिसे इसके पश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाते हुए 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात् अधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है और संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने हेतु अनुरोध किया है ।

और यतः प्राधिकारी पाते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और पाटन व क्षति के बीच कारणात्मक संबंधों के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं; प्राधिकारी एतद्वारा उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति के बारे में जांच की शुरुआत करते हैं

ताकि किसी कथित पाटन की विद्यमानता, परिमाण और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की राशि का निर्धारण किया जा सके जिसे लगाने पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति पर्याप्त रूप से निष्प्रभावी हो जाए ।

2. विचाराधीन उत्पाद

वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क-रिकॉर्डेबल है । इन उत्पादों में डीवीडी-आर, डीवीडी+आर, डीवीडी-आरडब्ल्यू और डीवीडी+आरडब्ल्यू को भी शामिल किया जा सकता है । ये डिस्कें एक साइड वाली अर्थात् एक तरफ रिकार्ड करने योग्य और सूची और डमी, तथा दुहरे साइड वाली अर्थात् दोनों तरफ रिकार्ड करने योग्य हो सकती हैं । ये डिस्कें पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक सामग्री की बनी होती हैं । पॉलीकार्बोनेट डिस्क में सूचना को लिखने तथा पढ़ने के लिए लेसर किरण को निर्देशित करने वाली सर्पिल ग्राव रहती है । डिस्क को अत्यंत पतली वनस्पति आधारित कार्बनिक रंजक पर्त और इसके पश्चात् चांदी, चांदी मिश्र धातु अथवा सोने की पतली प्रतिबिम्बित पर्त के साथ सर्पिल ग्राव से विलेपित किया जाता है ।

याचिकाकर्ता ने बताया है कि संबद्ध वस्तु का आयात सीमाशुल्क वर्गीकरण के अध्याय 8523 के अंतर्गत निम्नांकित उप शीर्षकों के साथ किया जा रहा है :

85232920, 85232950, 85232970, 85234040, 85234050, 85234060, 85234080, 85234090, 85238090, 85235290, 85238050, 85239010, 85239040, 85239090

तथापि, उपर्युक्त केवल संकेतात्मक है और जांच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है ।

यह उत्पाद आंकड़ों के संख्यात्मक संग्रहण के लिए प्रयुक्त किया जाता है और इसके व्यापक अनुप्रयोग हैं ।

3. घरेलू उद्योग एवं इसकी स्थिति

आवेदन ऑप्टिकल मैन्यूफैक्चर्स वेल्फेयर एसोसिएशन, नई दिल्ली, (ओडीएमडब्ल्यू) जिसमें भारत में संबद्ध वस्तु के तीन उत्पादक मै. मोजर बेअर, मै. यूरो मल्टी-विजन और मै. कम्प्यूटर स्किल शामिल हैं, द्वारा दाखिल किया गया है। मै. मोजर बेअर मुख्य उत्पादक है। मै. मोजर बेअर ने याचिका पर विचार करने के लिए अपेक्षित तथ्य एवं आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। घरेलू उद्योग नियमों के अंतर्गत यथाउपबंधित अपेक्षित न्यूनतम से अधिक संबद्ध वस्तु का उत्पादन कर रहा है। अतः याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तु के सम्पूर्ण उत्पादन के लिए जिम्मेदार है और यह नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है।

4. समान वस्तु

याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि वैश्विक रूप से सभी डीवीडी-आर ऑरिज बुक में दिए गए विनिर्देशन के अनुरूप होती हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानक अन्तर्निहित होते हैं। याचिकाकर्ता कम्पनी द्वारा उत्पादित डीवीडी-आर तथा संबद्ध देशों से पाटित आयातों में समान भौतिक एवं तकनीकी विशेषताएँ हैं और इनका कार्य एवं प्रयोग भी समान है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित डीवीडी-आर तथा संबद्ध देशों से आयातित डीवीडी-आर में कोई खास अंतर नहीं है। ऐसी सभी डीवीडी तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं तथा उपभोक्ता उन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद तथा संबद्ध देशों/क्षेत्रों से आयातित उत्पाद सभी मूल विशेषताओं में समान होने के कारण इन्हें नियमावली के अनुसार शब्द के अर्थ के भीतर समान वस्तु माना जाता है।

5. सामान्य मूल्य

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीनी उत्पादों के पाटन के लिए भारत एक उपयुक्त प्रतिनिधि देश है और इसलिए अपने इसके उत्पादकों को गैर-बाजार अर्थ व्यवस्था का दर्जा देने का अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता ने यह भी निवेदन किया है कि चीन पीआर में सामान्य मूल्य के निर्धारणार्थ भारत एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था देश है।

हांगकांग और ताईवान के संबंध में याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि उन्होंने सार्वजनिक सूत्रों से निर्यातकों या विनिर्माताओं की कीमत सूची या अन्य देशों को अपने निर्यातों के लिए कीमत साक्ष्य या कोई अन्य सूचना प्राप्त करने के प्रयास किए हैं। तथापि, वे वास्तविक सौदेवार कीमत जिस पर संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों के घरेलू बाजारों में बेची जा रही है या उनके द्वारा अन्य देशों को निर्यात की जा रही है, का प्रामाणिक, पर्याप्त एवं सही साक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे हैं। चूंकि घरेलू उद्योग तथा संबद्ध देशों के विनिर्माताओं द्वारा अपनायी गई प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात अंतर नहीं है, इसलिए भारतीय उत्पादों तथा विदेशों उत्पादकों के लागत ढांचे में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों के प्रचालन का पैमाना भी तुलनीय है। अतः याचिकाकर्ता ने सामान्य मूल्य के निर्धारणार्थ संबंधित देशों से भारत में पोलिकार्बोनेट्स के आयातों की औसत दर लेकर रचनात्मक मूल्य दृष्टिकोण अपनाया है।

6. शामिल देश

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन पी.आर., हांगकांग और ताईवान के निर्यातकों द्वारा पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तु का भारतीय बाजारों में निर्यात किया जा रहा है।

7. जांच अवधि

याचिकाकर्ता ने जांच अवधि अर्थात् 1 अप्रैल, 2006 से 30 जून, 2007 तक (15 महीने) के संबंध में सूचना दी है और निर्दिष्ट प्राधिकारी को तुलना करने में समर्थ बनाने के लिए वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 से संबंधित तथ्य एवं आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। जांच की अवधि प्रस्तावित जांच शुरुआत की तारीख से पहले छह महीने के भीतर है।

8. निर्यात कीमत

याचिकाकर्ता ने अवतरण प्रभार, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन व्यय तथा बैंक कमीशन के समायोजनों के दावे के बाद मै. इम्पेक्स स्टेटिस्टिक्स सर्विसेज, मुम्बई द्वारा संग्रहीत आंकड़ों के आधार पर संबद्ध वस्तु का निर्यात निर्धारित किया है।

9. पाटन मार्जिन

आवेदकों द्वारा प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए सकारात्मक प्रमाण के आधार पर प्रतीत होता है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य भारत में शुद्ध निर्यात कीमतों से बहुत अधिक है जो प्रथमदृष्ट्या इस बात को दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। पाटन मार्जिन सकारात्मक तथा न्यूनतम से अधिक होने का अनुमान है।

10. क्षति तथा कारणात्मक संबंध

याचिकाकर्ताओं ने जाँचाधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग को हुई क्षति से संबंधित विभिन्न मानकों तथा संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा तथा मूल्य के बारे में सूचना प्रस्तुत की है। निरपेक्ष रूप से आयातों की मात्रा में वृद्धि, अप्रयुक्त संस्थापित क्षमता, कीमत अवमूल्यन तथा ह्रास, कीमत कटौती, वस्तु सूचियों का संग्रह, हानियों की स्थिति, निवेश पर ऋणात्मक आय आदि जैसे मानक प्रथमदृष्ट्या यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों ने मिलकर घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाई है।

11. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देशों/क्षेत्रों के निर्यातकों, उन देशों के दूतावासों/प्रतिनिधियों के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे सभी संबद्ध सूचना निर्धारित रूप तथा तरीके से प्रस्तुत कर सकें और निम्नांकित को अपने विचारों से अवगत करा सकें :-

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
कमरा सं. 240, उद्योग भवन
नई दिल्ली - 110011

कोई अन्य हितबद्ध पक्ष भी निर्धारित रूप तथा तरीके से नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर जाँच से संबंधित आवेदन दे सकता है।

12. समय सीमा

मौजूदा जाँच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिन के भीतर ऊपर उल्लिखित पते पर भेज दी जानी चाहिए। परिचित समझे जाने वाले निर्यातक तथा आयातक, जिन्हें अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें लिखे गए पत्रों की तारीख से चालीस (40) दिन के भीतर सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं।

13. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

नियम 6 (7) के अनुसार हितबद्ध पक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सार प्राधिकारी को प्रस्तुत करें और यदि ऐसी सूचना देने वाले किसी पक्ष के विचार में किसी सूचना का सार बनाना संभव नहीं है तो उन्हें इसके कारण से संबंधित विवरण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई हितबद्ध पक्ष सूचना देने से मना करता है या समुचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रस्तुत नहीं करता अथवा जानबूझ कर जाँच में बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं और जैसा उचित समझें, केन्द्र सरकार से वैसी ही सिफारिश कर सकते हैं।

14. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के तहत कोई भी हितबद्ध पक्ष सार्वजनिक फाइल को देख सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणों का अगोपनीय सार होता है।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2007

Subject: Initiation of anti-dumping investigation involving import of Digital Versatile Discs—Recordable (DVD-R) from China PR, Hong Kong and Taiwan.

Initiation

No. 14/17/2007-DGAD.—Whereas Optical Disc Manufacturers Welfare Association (ODMWA) New Delhi (hereinafter referred to as the Applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as this Authority), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as Rules), alleging dumping of Digital Versatile Discs Recordable (DVD-R) (hereinafter referred to as subject goods), originating in or exported from the China PR, Hong Kong and Taiwan (herein after referred to as subject countries) and requested for initiation of Anti-Dumping investigations for levy of anti-dumping duties on the subject goods.

And whereas, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods from the subject countries, injury to the domestic industry and

causal links between the dumping and injury exist, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the said Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

2. Product under consideration

The product under consideration in the present petition is Digital Versatile Disc Recordable of all kinds. Such product may include DVD-R, DVD+R, DVD-RW and DVD+RW. Such discs may be single sided i.e. recordable on one side and dummy on the other side, and double sided i.e. recordable on both the sides. Such discs are made of polycarbonate plastic material. The polycarbonate disc contains a spiral groove to guide the laser beam for writing and reading information. The disc is coated with the spiral groove with a very thin layer of vegetable based organic dye and subsequently with a thin reflecting layer of silver, a silver alloy or gold.

The petitioner has stated that import of the subject products is being made under Chapter 8523 of the Customs Classification with the following subheading :

85232920, 85232950, 85232970, 85234040, 85234050, 85234060; 85234080, 85234090, 85238090, 85235290, 85238050, 85239010, 85239040, 85239050 and 85239090.

However, the above said is only indicative and is in no way binding on the scope of the investigation.

Such product is used for storing data digitally and has wide usage.

3. Domestic industry and standing

The application has been filed by Optical Disc Manufacturers Welfare Association, New Delhi, (ODMWA) comprising of three producers of the subject goods in India M/s. Moser Baer, M/s. Euro Multi-vision and M/s. Computer Skill. M/s. Moser Baer is the main producer. M/s. Moser Baer has provided the required facts and figures for processing of the petition. The domestic industry is producing subject goods more than the required minimum as provided under the rules. The petitioner, therefore, accounts for complete production of subject goods in India and constitutes domestic industry within the meaning of the Rules.

4. Like article

The petitioner has submitted that globally all DVD-R comply with the specification given in the orange book which contains international standards. The DVD-R produced by the petitioner company and the dumped imports from the subject countries have similar physical and technical characteristics, functions and uses. There is no significant difference between the DVD-R produced by the petitioner and those imported from the subject countries. All such DVDs are technically and commercially substitutable with the consumers using them interchangeably. The products produced by the domestic industry and imported from subject Countries/territories

being identical in all essential characteristics are treated as like article within the meaning of the term as per the Rules.

5. Normal value

The petitioner has claimed that India is an appropriate surrogate country for dumping of Chinese products and hence has requested for giving non-market economy status to its producers. The petitioner has further submitted that India is an appropriate market economy country for determination of normal value in China PR.

Regarding Hong Kong and Taiwan, the petitioner has submitted that they have made efforts to get price lists of the exporters or manufacturers or price evidence for their exports to other countries or any other information from the public sources. However, they have not been able to get an authentic, adequate and accurate evidence of actual transaction wise price at which the subject goods are being sold in the domestic markets of the subject countries or being exported by them to other countries. Since there is no known difference in the technology adopted by the DI and manufacturers of the subject countries, there is no significant difference in the cost structure of the Indian produces and the foreign producers. The scale of operations of the two is also comparable. Therefore, the petitioner has adopted constructive value approach for determination of the normal value taking average rate of imports of poly carbonates into India from the respective countries.

6. Countries involved

The petitioner has claimed that the subject goods are being exported to the Indian markets at dumped prices by the exporters from China PR, Hong Kong and Taiwan.

7. Period of Investigation

The petitioner has given information for the period of investigation i.e. 1st April 2006 to 30th June 2007 (15 months) and has also made available facts and figures pertaining to 2003-04, 2004-05 and 2005-06 for enabling the Designated Authority to make comparisons. The period of investigation is within six months prior to the date of proposed initiation.

8. Export price

The petitioner has worked out export of the subject goods on the basis of data compiled by M/s. Impex Statistics Services, Mumbai after claiming adjustments of landing charges, ocean freight, marine insurance, inland transportation, port expenses and bank commission.

9. Dumping margin

On the basis of positive evidence placed by the applicants before the Authority it appears that the Normal Values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the net export prices to India, indicating prima-facie that the subject goods are being dumped in the Indian market by exporters from the subject countries. The dumping margins are estimated to be positive and above de minimis.

10. Injury and causal link

Petitioners have furnished information on volume and value of dumped imports from the subject countries and various parameters relating to injury to the domestic industry, on account of the product under consideration. Parameters, such as increase in volume of imports in absolute terms, unutilized installed capacity, price suppression and depression, price undercutting, piling up of inventories, position of losses, negative return on investment etc. prima-facie indicate that the dumped imports of the subject goods from the subject countries have cumulatively injured the Domestic Industry.

11. Submission of information

The exporters in the subject Countries/territories, their governments through their embassies/ representatives in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are requested to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the :

Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Room No. 240, Udyog Bhavan,
New Delhi-110107.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

12. Time limit

Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty (40) days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however, required to submit the information within (40) forty days from the date of the letter addressed to them.

13. Submission of information on non-confidential basis

In terms of Rule 6(7), of the Rules the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summary, a statement of reason thereof is required to be provided. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

14. Inspection of public file

Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties in terms of Rule 6 (7).

R. GOPALAN, Designated Authority